Title: Raised a matter regarding budgetary hike in Urea price and the Finance Minister made a statement in the House.

15.28 hrs.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Rajesh Pilot, would you like to raise some point or you want the hon. Finance Minister to make a statement?

SHRI RAJESH PILOT (DAUSA): During Zero Hour, we have raised it and the hon. Speaker has assured us that the hon. Finance Minister would come and answer.

श्री राजेश पायलट सारे सदन की भावना आपने सुनी है। चाहे इस पार्टी के एम.पी.हैं, चाहे उस पार्टी के एम.पी. हैं, सब ने एक स्वर से यह कहा है कि आपने कल जो यूरिया के दाम एक रुपए प्रति किलो बढ़ाए हैं, वह किसान के ऊपर एक बोझ है। सारा सदन यह महसूस करता है कि यह किसान के ऊपर बोझ है और इसे कम किया जाना चाहिए। भाई यशवन्त सिन्हा जी के दिल से यह बात नहीं निकली है, यह तो इन्हें किसी मजबूरी के कारण करना पड़ा होगा। कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस बन गए होगे जिनके कारण इन्हें यह करना पड़ा। मैं चाहूंगा कि सारे सदन की भावना को देखते हुए और कृषि राज्य मंत्री महोदय की साइंटीफिक एप्रोच पर न जाते हुए श्री यशवन्त सिन्हा जी इसे कंसीडर करें और किसानों के ऊपर यूरिया का एक रुपए प्रति किलो दाम बढ़ाकर लादे गए इस बोझ को रोल बैक करें।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि किसानों के साथ थोड़ी ज्यादती हो गई है। एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर के लिए हम सब कह रहे हैं। आपने वित्त मंत्री जी कल अपने भाषण में भी कहा कि अगर एग्रो बेस्ड को हम ५८ परसेंट उठाना चाहते हैं, तो इस एग्रो बेस्ड एग्रीकल्चर को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। अगर ऐसा करना है, तो इसको टैक्स से बाहर रखना पड़ेगा, लेकिन कल आपका जब भाषण चल रहा था, तो मैं पूरी तरह से समझ नहीं सका क्योंकि आपने कुछ फूड आयटम्स पर एक्साइज बढ़ाई है। अगर एग्रो बेस्ड को डिवेलप करना है, तो आपको इस क्षेत्र को टैक्स मुक्त करना पड़ेगा। यदि आप इस क्षेत्र को विकसित करना चाहते हैं, तो आप इस क्षेत्र में किसी प्रकार का टैक्स न लगाएं, तभी एग्रो बेस्ड पनपेगा। मुझे लगता है कि किसी गलतफहमी की वजह से सरकार ने ट्रैक्टर के रेट बढ़ा दिए हैं। पिछली कई सरकारों ने ट्रैक्टर के रेट नहीं बढ़ाए हैं।

सभापति महोदय, इस प्रकार से मैंने ये तीन-चार चीजें वित्त मंत्री महोदय के ध्यान में लाई हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इनके ऊपर सहानुभूति पूर्वक विचार कर लें।

MR. CHAIRMAN: Please sit down. No interruptions, please.

... (Interruptions)

">

श्रीमती कैलाशो देवी (कुरूक्षेत्र): सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्री महोदय इन बातों पर विशेष रूप से विचार करें क्योंकि यदि किसान खुशहाल होगा, तो ही देश खुशहाल बनेगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि मंत्री महोदय किसानों को राहत देने के मामले पर प्रायर्टी से विचार करें।

SHRI INDRAJIT GUPTA (MIDNAPORE): Could I just take one minute before the hon. Finance Minister starts his speech?

MR. CHAIRMAN: Hon. Speaker has assured Shri Rajesh Pilot that the hon. Finance Minister would reply. We have to take up Private Members' Business at 1530 hours. Every one will get a chance to raise the issue when we take up the Budget for discussion.

SHRI INDRAJIT GUPTA : Let me raise the point, then we can deal with the same later on.

MR. CHAIRMAN: All right.

">

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सभापति जी, अगर मैंने गलत नहीं सुना और अगर गलत सुना है तो मुझे सुधार दें, वित्त मंत्री जी ने, कल घोषणा की थी और उनका छपा हुआ जो भाषण था उसमें आया है कि यूरिया पर एक रुपये पर किलोग्राम टैक्स लगा है, टैक्स बोलिये या और कुछ बोलिये लेकिन आज मैंने सुना जब वह बोल रहे थे कि वह उसे घटाकर एक रुपये के बजाए ५० पैसे करने को तैयार हैं। मैं केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब उन्होंने कल बजट फार्मली पेश किया

है, बजट प्रपोजल के हिसाब से आ गया है तो क्या वित्त मंत्री को संविधान के अनुसार कानूनी अधिकार है कि वह यह काम कर सकते हैं? जब वह फाइनेंस बिल को लायेंगे तो उसमें संशोधन कर सकते हैं। फाइनेंस बिल में तो एक रुपया चला जायेगा। उसे घटाकर अगर ५० पैसे करना है तो वह उसको फाइनेंस बिल में अमेंडमैंट लाकर कर सकते हैं। उसमें कुछ भी हो लेकिन सुओमोटो यहां ऐसे भाषण के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। तब यह बजट प्रपोजल की कोई पवित्रता, कोई सेंक्टिटी नहीं रहती। यह एक गलत बात है।

">

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): सभापति जी, किसानों के लिए इस सरकार को जो चिन्ता है उसे हमने बहुत सारे शब्दों में कल सदन के सामने रखा था और यदि माननीय सदस्य गौर से मेरे बजट प्रस्तावों को देखें तो वह पायेंगे कि न केवल बजट के जो प्रावधान हैं, उनको बढ़ाकर बल्कि पूरे रूरल क्रेडिट व्यवस्था को और बेहतर बनाकर मैंने यह एक गंभीर प्रयास किया है कि किसानों के सामने जो समस्याएं हैं, उनसे उनको मुक्ति मिले। यहां आज हम दिन भर किसानो की आत्महत्या के सवाल पर बहस कर रहे हैं। उसी बिन्दु को ध्यान में रखते हुए कल मैंने अपने बजट भाषण में कहा था कि अब

किसान इस देश में आत्महत्या करने के लिए बाध्य नहीं होगा, न किसी किसान को हम सिविल जेल भेजेंगे, इसलिए कि उसके पास कुछ ऋण बकाया रह गया है। यहां यह प्रश्न नहीं उठा था लेकिन मैंने देश के कई भागों में देखा है, मैंने अपने प्रदेश में देखा है कि किसान खेत का काम छोड़कर, जब बोआई का टाइम है या कृषि के और कार्यों का टाइम है, खेत को छोड़कर जंगलों में भाग जाते हैं क्योंकि उनके पीछे प्रशासन उनको जेल में डालने के लिए लगा रहता है। यह दर्द मेरे अंदर था। इसलिए मैंने कहा कि कोई किसान आगे से इस सरकार के रहते हुए जेल भी जाने के लिए बाध्य नहीं होगा, मरने की बात, आत्महत्या की बात तो छोड़ दीजिए। जो सवाल यहां पर यूरिया का उठाया गया, मैं सदन के सामने नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें हजार, दो हजार करोड़ रुपये सरकार को प्राप्त हो जायेंगे, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि १९५१ से फर्टिलाईजर की कीमतों को तय करने के लिए जो नीतियां चलाई गयीं, उन नीतियों के चलते एम.पी. के जो रेशो हें, जो आदर्श अपने आप में चार, दो, एक का है, वह आसमान की तरफ भाग गया है। पता नहीं कितने डिस्टोर्शन उसमें आ गये हैं कि अब वह दस,दो,एक हो गया। जैसे कि मेरे मित्र सहयोगी सोमपाल जी कह रहे थे कि उसके चलते इसी देश में कितनी स्टडीज हुई हैं। इधर से कह रहे हैं कि हमने सुधार नहीं किया तो फिर जो हमारी भूमि की उर्वरकता है, उसके ऊपर गंभीर असर पड़ेगा और अगर यहां सारा रेगिस्तान बन जाता है तो उसकी जिम्मेदारी हम सब सदन में बैठे हुए लोगों की है चाहे कोई भी सरकार में हो। यहां जितने लोग बैठे हैं, चाहे उस तरफ के लोग सरकार में रहे हैं, इस तरफ के लोग रहे हैं आज इस तरफ के लोग हैं, हम सब इस बात के लिए जिम्मेदार होंगे कि समय पर हमने इसकी चिन्ता नहीं की।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हजार दो हजार रुपये भारत सरकार के बजट के लिए कोई औकात नहीं रखते। लेकिन इस बात के लिए कि हमारे किसान यूरिया की खपत थोड़ी कम करे और बाकी जो उर्वरक हैं, उनकी खपत कुछ अधिक हो और उनकी कीमतों में जो भारी डिस्टोर्शन आ गया है, उसको हम पाट सकें, इस दृष्टिकोण से हमने यह कदम उठाया था।

श्मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन का एक स्टडी ग्रुप बना था, जिसने कहा था कि आठवीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होते-होते यूरिया की कीमतों में ३० प्रतिशत की व्रद्धि होनी चाहिए। जब यह स्टडी ग्रुप बना था और उसने इस तरह की सिफारिश की थी, उस समय हम सरकार में नहीं थे। लेकिन फिर भी मैं इतना कहना चाहूंगा कि यहां आने से पहले जब हमने सारी भावनाओं पर विचार किया, फिर सदन में मैंने यहां की भावना देखी तो मैंने तत्काल इस सदन में इस बात की घोषणा कर दी। अब इसे कार्यान्वित कैसे करेंगे, मैं इंद्रजीत गुप्ता जी से कहना चाहूंगा कि यह घोषणा है, कार्यान्वयन नहीं है। जब बजट पर चर्चा होगी तो इसे कार्यान्वित करने का सही तरीका ढूंढकर हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन मैंने इस बात की घोषणा करना आवश्यक समझा कि जहां हमारा पूरा बजट किसानोन्मुख है, किसानों की मदद के लिए है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए है और पूरे देश में आज के दिन इस बजट के बारे में यही भावना है, इस बारे में कोई गलत प्रचार न हो। इसीलिए मैंने कहा कि मैंने कल व्रद्धि की जो घोषणा की थी, उसे मैं ५० प्रतिशत रोल बैक कर रहा हूं। यह घोषणा मैंने सदन के सामने कर दी। मुझे लगता है कि किसानों की मित्रता के भाव से जो बजट पेश किया गया है, उसे हम सही अर्थ में देखें और कृपया इसमें राजनीति को नहीं लाएं। हम यहां पर जब किसानों की आत्महत्या की बात करते हैं तो क्या वह राजनीति का मुद्दा है? किसान जब जेल जाता है तो क्या वह राजनीति का मुद्दा है? किसानों का मुद्दा राजनीति का मुद्दा नहीं है, किसानों का मुद्दा देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश की सामाजिक व्यवस्था के लिए सर्वोपरि, सर्वोच्च प्राथमिकता का मुद्दा है और मैं चाहूंगा कि सदन उसे उसी भाव से ले।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने कोई राजनीतिक बात नहीं उठाई, मैंने वैधानिक बात उठाई है।

... (व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा: मैं आपको नहीं कह रहा हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप इस ढंग से अपने प्रपोज़ल को नहीं बदल सकते। ... (व्यवधान)

SHRI N.K. PREMCHANDRAN (QUILON): Sir, this is not the situation of the farmers. ...(Interruptions)

श्री अजीत जोगी (रायगढ़): यह सबसे ज्यादा किसान विरोधी बजट है।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Raghuvansh Prasad Singh, please hear the Minister of Finance first.

... (Interruptions)

श्री यशवंत सिन्हाः मैं कहना चाहता हूं कि यदि यह किसान विरोधी बजट है तो २५.७.९१ को यूरिया की कीमत जो ३,३३० हो गई, १४.८.९५ को फिर आगे बढ़ी, तो यह क्या पौलीटिक्स है।

... (व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record. No further discussion on this matter.

(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: Now, we shall take up Private Members' Business.

---

* Not recorded